वेबसाईट : www.abvp.org पंजीकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय– 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई–मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 25 फरवरी 2023

-:प्रेस विज्ञप्ति:-

अभाविप ने देशभर में सीयूईटी-यूजी के परीक्षा केंद्रों (शहरों) को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यूजीसी अध्यक्ष को लिखा पत्र।

सीयूईटी परीक्षाएं सरकारी तथा विश्वसनीय संस्थानों में हों आयोजित: अभाविप।

पूर्वोत्तर भारत में सीयूईटी-यूजी परीक्षा केंद्रों की संख्या कम, बढ़ाए जाएं परीक्षा केंद्र: अभाविप।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूजीसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली सीयूईटी-यूजी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों(शहरों) को बढ़ाए जाने, परीक्षाएं सरकारी तथा विश्वसनीय संस्थानों में ही आयोजित करने व परीक्षा अधिकारी के तौर पर केन्द्र व राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारी नियुक्त करने आदि मांगें रखी हैं।

वर्तमान समय में देश की विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन एनटीए के माध्यम से किया जा रहा है, अतः सीबीटी मोड में परीक्षाएं आयोजित करने के लिए वर्तमान में देश में विभिन्न शहरों में परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाने तथा डिजिटल आधारभूत ढांचे में तेजी से विकास की आवश्यकता है। हाल में विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन एनटीए द्वारा कराए जाने के दौरान सामान्यतः यह समस्या देखी गई कि कम्प्यूटर आधारित परीक्षा कराने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वसनीय कम्प्यूटर लैबों की कमी है,विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों की दूरी आदि के कारण अनेक समस्याएं हो रही हैं।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि, "सीयूईटी यूजी के लिए एनटीए ने कम परीक्षा केंद्र बनाए हैं। अभाविप की मांग है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए तथा पूर्वोत्तर भारत सहित देश के अलग-अलग राज्यों में परीक्षा आयोजन के दौरान यह ध्यान रखा जाए कि छात्रों के लिए उनके नजदीकी शहरों में परीक्षा केंद्र का विकल्प उपलब्ध हो व देशभर में परीक्षा शत-प्रतिशत पारदर्शी ढंग से आयोजित हो। सीयूईटी यूजी व पीजी तथा यूजीसी नेट आदि के लिए परीक्षा केंद्रों को बढ़ाए जाने संबंधी अभाविप की मांग पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा एनटीए को शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय कार्यालय मंत्री श्री दिगंबर पवार द्वारा जारी की गयी है।)